भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2777**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए
चीन से उत्पाद आयात

2777. श्री पुट्टा महेश कुमारः

क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान चीन से आयातित उत्पादों की कुल मात्रा और मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान भारत में चीन से आयातित कुल कितने उत्पादों की गुणवत्ता दोषपूर्ण/घटिया पाई गई है;
(ग) चीन में बने घटिया/दोषपूर्ण उत्पादों के कारण भारतीय बाजारों को कुल कितना घाटा हुआ है;
(घ) भारत के उन प्रमुख क्षेत्रों की सूची का ब्यौरा क्या है जो देश में वस्तुओं की एसेम्बली/उत्पादन के लिए चीन के उत्पादों पर निर्भर हैं; और
(ङ) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान भारतीय बाजारों में चीन में निर्मित उत्पादों पर निर्भरता को कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क): विगत पांच वर्षों के दौरान चीन से आयातित उत्पादों की कुल मात्रा और मूल्यांकन का ब्यौरा वाणिज्य विभाग की वेबसाइट अर्थात https://tradestat.commerce.gov.in/eidb/icntcomq.asp. से देखा जा सकता है।

(ख) से (ङ): सरकार ने गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण प्रोटोकॉल और अनिवार्य प्रमाणन के लिए कठोर गुणवत्ता मानकों और उपायों को लागू किया है ताकि अवमानक आयात को नियंत्रित किया जा सके। भारत में अवमानक उत्पादों के आयात को कम करने के लिए संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा

इस्पात, खिलौने, रसायन, चमड़ा और जूते आदि जैसे कई उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) लागू किए गए हैं।

चीन से आयातित अधिकांश वस्तुएं, कच्ची सामाग्रियां, इंटरमीडिएट वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं जैसे सक्रिय फार्मास्युटिकल इंग्रिडिऐन्टस, ऑटो घटक, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और एसेम्बलीज, मोबाइल फोन पार्ट्स, मशीनरी और उसके पार्ट्स, आदि है जिनका उपयोग परिसज्जित उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है, जिनका भारत से बाहर भी निर्यात किया जाता है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, दूरसंचार और बिजली जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं का आयात किया जाता है। इन श्रेणियों में आयात पर भारत की निर्भरता मुख्य रूप से घरेलू आपूर्ति और मांग के कारण है।

घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, भारत सरकार ने अनेक पहलों जैसे 'मेक इन इंडिया' पहल की शुरूआत की हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, व्हाइट गुड्स, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों आदि जैसे 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रोडक्शन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम शुरू की है, जहां आयात पर अत्यधिक निर्भरता है। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए, सरकार ने 76,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है।

सरकार नियमित आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में आयात में वृद्धि की निगरानी करती है और उपयुक्त कार्रवाई भी करती है। इसके अलावा, व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) को अनुचित व्यापार परिपाटियों के विरूद्ध व्यापार उपचारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने की शक्ति प्रदान की गई है।

******